राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रेफरेंस नंबर 5/2020

देवनारायण शर्मा पुत्र कंवरी लाल, निवासी पीपलू, तहसील पीपलू, जिला टोंक (राज.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. रामफूल पुत्र रोड़ू, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
2. हीरालाल पुत्र रोड़ू, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
3. प्रहलाद पुत्र रोड़ू, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
4. बादाम पुत्री रोड़ू, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
5. मनफूल पुत्री रोड़ू, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
6. मनभर पुत्री रोड़ू, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
7. भंवर लाल पुत्र रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
8. छोटू पुत्र रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
9. रामकंवर पुत्री रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)
10. ममता पुत्री रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

11. श्रावणी पुत्री रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)

12. शांति पुत्री रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)

13. सायर पुत्री रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)

14. भागुली पत्नी स्वर्गीय रामलाल, निवासी पीपलू वर्तमान निवासी ग्राम अरनियातीवाड़ी, तहसील और जिला टोंक (राज.)

15. राजूलाल पुत्र छोटू, निवासी पीपलू, जिला टोंक (राज.)

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री संदीप जैन,
श्री मनोज भारद्वाज,
श्री राहुल कंवर,
श्री आलोक चतुर्वेदी,
श्री मनीष शर्मा,
श्री लक्ष्य पारीक,
श्री श्रेयांश शर्मा,
श्री नकुल कौशिक,
श्री राजेश चतुर्वेदी,
श्री पंकज अग्रवाल,
श्री पंकज कुमार,
श्री अनीश भडाला,
श्री ओ.पी. मिश्रा,
श्री रोहिताश कुमार,
श्री तपिश सारस्वत,
सुश्री मीता पारीक,
श्री प्रशांत शर्मा,

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

		श्री अभिलेश शर्मा, श्री विमल कुमार जैन, श्री गौरव जैन, श्री रोहिताश सैनी, श्री दिवांशु गुप्ता, श्री राजेश शर्मा, सुश्री शुभी गौड़, श्री फारूक अहमद।
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री बसंत सिंह छाबा, एएजी के साथ श्री हार्दिक सिंह, श्री प्रवीण कुमार जैन।

माननीय श्री न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश

आरक्षित किया गया :: **22/02/2024 को**

सुनाया गया :: **11/03/2024 को**

(न्यायमूर्ति पंकज भंडारी के द्वारा)

रिपोर्ट करने योग्य

1. इस न्यायालय के विभिन्न एकल पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया:

> "क्या वादी को राजस्थान कोर्ट फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार केवल मुख्य राहत के मूल्य पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा और विभिन्न राहतों के कुल मूल्य के आधार पर नहीं?"

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

2. दिनांक 16.10.2019 के आदेश के अनुसार, पक्षों के विद्वान वकील के अनुरोध पर, वर्तमान मामले में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित शब्दों में फिर से तैयार किया गया था:

> "1. क्या वादी को राजस्थान कोर्ट फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) के अनुसार वाद में मांगी गई विशिष्ट और अलग-अलग राहतों के कुल मूल्य पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा या क्या विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए मांगी गई राहत केवल बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मुख्य राहत के लिए सहायक होने के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार केवल मुख्य राहत पर ही कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा?
>
> "2. क्या वादी के पक्ष में बिक्री के समझौते के बाद निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ एक विशिष्ट राहत के लिए एक वाद में, वादी को राजस्थान कोर्ट फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 38 के अनुसार विक्रय विलेख में घोषित संपत्ति के मूल्य पर एड-वेलोरम आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा?"

3. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को बार के उन सदस्यों की जानकारी के लिए एक नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था, जो उपरोक्त प्रश्नों पर न्यायालय को संबोधित करने के इच्छुक हो सकते हैं। नोटिस के परिणामस्वरूप, बार के सदस्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उन्होंने सहायक केस कानूनों के साथ अपने लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किए हैं।

4. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील, श्री प्रवीण जैन ने तर्क दिया कि राजस्थान कोर्ट फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (इसके बाद '1961 का अधिनियम') की धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार, यदि मांगी गई राहत मुख्य राहत के लिए सहायक है, तो वाद केवल मुख्य राहत के मूल्य पर ही शुल्क योग्य होगा। यह भी तर्क दिया गया है कि एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद में जहां प्रार्थना बाद के विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए है, वही एक घोषणात्मक राहत है, जो न्यायालय से मांगी गई है और यह मुख्य राहत यानी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के लिए सहायक है। यह आगे तर्क दिया गया है कि विक्रय विलेख को रद्द करना और विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करना दो अलग-अलग राहतें हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय विलेख का एक पक्ष है, तो उसे विक्रय विलेख को रद्द करने

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

के लिए एक वाद दायर करना होगा और उस मामले में, उसे एड-वेलोरम कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति विक्रय विलेख का एक पक्ष नहीं है, तो वह विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए एक वाद दायर कर सकता है। उस मामले में, मुख्य राहत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए होगी और विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की राहत एक सहायक राहत होगी और कोर्ट फीस मुख्य राहत के मूल्य पर देय होगी।

5. श्री मनोज भारद्वाज, अधिवक्ता; श्री टी.एल. पांडे, अधिवक्ता; श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता; सुश्री मीता पारीक, अधिवक्ता; श्री दिवांशु गुप्ता, अधिवक्ता; श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता; सुश्री शुभी गौड़, अधिवक्ता के साथ-साथ श्री लेखराज देवासी और सुश्री वर्तिका शर्मा, विधि इंटर्न द्वारा लिखित निवेदन दायर किए गए हैं।

6. श्री मनोज भारद्वाज, अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की राहत एक सहायक राहत है और इस प्रकार, 1961 के अधिनियम की धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार सहायक राहत के लिए कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 19 के अनुसार विक्रेता के साथ-साथ बाद के क्रेता के खिलाफ भी एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद दायर किया जा सकता है और ऐसा वाद 1961 के अधिनियम की धारा 6(1) के तहत एक बहुविध वाद की श्रेणी में नहीं आता है। यह आगे तर्क दिया गया है कि एक बार, बाद के पंजीकृत विक्रय विलेख से पहले दर्ज किए गए बिक्री के समझौते के संबंध में एक विक्रय विलेख पंजीकृत हो जाता है, जिसे शून्य और अमान्य घोषित करने की मांग की गई है, तो पहले के समझौते के अनुसरण में पंजीकृत विक्रय विलेख समझौते की तारीख से संबंधित होगा, जैसा कि गुरदयाल सिंह और अन्य बनाम सेवा सिंह और अन्य: **एआईआर 1973 पंजाब और हरियाणा पी. 254** और दीना बनाम गुजाबा: **एआईआर 1926 नागपुर 95** में आयोजित किया गया था।

7. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता और सुश्री मीता पारीक, अधिवक्ता ने अपने लिखित निवेदन में सुहरिद सिंह @ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य: **2010 एआईआर (एससी) 2807** पर भरोसा किया है।

8. इसके विपरीत; श्री दिवांशु गुप्ता, अधिवक्ता; श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता और सुश्री शुभी गौड़, अधिवक्ता ने अपने लिखित निवेदन में उल्लेख किया है कि वादी को विशिष्ट

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

और अलग-अलग राहतों के कुल मूल्य पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है और यह कि विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की राहत को बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत के लिए सहायक नहीं कहा जा सकता है।

9. प्रश्न संख्या 2 के संबंध में, विद्वान वकीलों ने अपने लिखित निवेदन में उल्लेख किया है कि 1961 के अधिनियम की धारा 38 लागू होगी और वादी को विक्रय विलेख में घोषित संपत्ति के मूल्य पर एड-वेलोरम आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा। उनके लिखित निवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि 1961 के अधिनियम की धारा 24 एक सामान्य प्रावधान है, जो विशेष रूप से किसी भी दस्तावेज़ को रद्द करने की परिकल्पना नहीं करता है और यह अन्य प्रकार की घोषणात्मक राहतों के लिए है, जिनका रद्द करने से कोई लेना-देना नहीं है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने रतन देवी बनाम गवरा देवी और अन्य: **2015 एआईआर (राजस्थान) 29**; महेंद्र सिंह राणावत बनाम भगवती देवी: **2017 (1) डीएनजे 337**; सुख लाल और अन्य बनाम देवी लाल और अन्य: **1954 एआईआर (राजस्थान) 170** और जे. वसंती और अन्य बनाम एन. रमानी कंथम्मल (डी) रेफ. बाय एलआरएस और अन्य: **2017 एआईआर (एससी) 3813** पर भरोसा किया है।

10. हमने तर्कों पर विचार किया है। संदर्भ का उत्तर देने के लिए प्रासंगिक धाराओं को नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

11. 1961 के अधिनियम की धारा 6(1) के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:

> "धारा 6. बहुविध वाद- (1) किसी भी वाद में जिसमें एक ही कारण के आधार पर अलग और विशिष्ट राहतें मांगी जाती हैं, वाद पत्र राहतों के कुल मूल्य के साथ शुल्क योग्य होगा:
>
> बशर्ते कि, यदि कोई राहत केवल मुख्य राहत के लिए सहायक के रूप में मांगी जाती है, तो वाद पत्र केवल मुख्य राहत के मूल्य पर ही शुल्क योग्य होगा। 2....."

12. अन्य धाराएं, जो संदर्भ का उत्तर देने के लिए प्रासंगिक हैं, वे हैं 1961 के अधिनियम की धारा 24(ई), 38(1) और 40 और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 19। उन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> **"धारा 24. घोषणा के लिए वाद:-**
>
> (ई) अन्य मामलों में, चाहे वाद का विषय-वस्तु मूल्यांकन के योग्य हो या नहीं, शुल्क उस राशि पर संगणित किया जाएगा जिस पर वाद पत्र में

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

मांगी गई राहत का मूल्यांकन किया गया है, बशर्ते कि न्यूनतम शुल्क पच्चीस रुपये हो।"

"धारा 38. डिक्री, आदि को रद्द करने के लिए वाद-
(1) धन या अन्य संपत्ति के लिए एक डिक्री को रद्द करने के लिए एक वाद में जिसका एक धन मूल्य है, या अन्य दस्तावेज़ जो धन, चल या अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित को वर्तमान या भविष्य में बनाने, घोषित करने, सौंपने, सीमित करने या बुझाने का इरादा रखता है या संचालित करता है, शुल्क वाद के विषय-वस्तु के मूल्य पर संगणित किया जाएगा, और ऐसे मूल्य को माना जाएगा-
(ए) यदि पूरी डिक्री या अन्य दस्तावेज़ को रद्द करने की मांग की गई है, तो वह राशि या संपत्ति का मूल्य जिसके लिए डिक्री पारित की गई थी या अन्य दस्तावेज़ निष्पादित किया गया था; और
(बी) यदि डिक्री या अन्य दस्तावेज़ के एक हिस्से को रद्द करने की मांग की गई है, तो राशि या संपत्ति के मूल्य का ऐसा हिस्सा।"

"धारा 40. विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद- एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद में, चाहे कब्जे के साथ या बिना, शुल्क देय होगा-

(ए) बिक्री के एक अनुबंध के मामले में, विचार की राशि पर संगणित;

(बी) बंधक के एक अनुबंध के मामले में, बंधक द्वारा सुरक्षित की जाने वाली सहमत राशि पर संगणित;

(सी) पट्टे के एक अनुबंध के मामले में, जुर्माने या प्रीमियम की कुल राशि पर, यदि कोई हो, और भुगतान की जाने वाली वार्षिक किराए के औसत पर संगणित;

(डी) विनिमय के एक अनुबंध के मामले में, विचार की राशि पर, या जैसा भी मामला हो, विनिमय में ली जाने वाली संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित;

(ई) अन्य मामलों में, जहां लागू किए जाने वाले वादे के विचार का बाजार मूल्य है, ऐसे बाजार मूल्य पर संगणित या जहां ऐसे विचार का कोई बाजार मूल्य नहीं है, तो धारा 45 में निर्दिष्ट दरों पर।

" विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 19 –

"19. पार्टियों और उनके तहत बाद के शीर्षक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ राहत।—जब तक कि इस अध्याय द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो, एक अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन इसके खिलाफ लागू किया जा सकता है—

(ए) इसके किसी भी पक्ष;

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

(बी) उसके तहत दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो अनुबंध के बाद उत्पन्न होने वाले शीर्षक द्वारा, सिवाय एक मूल्य के लिए एक हस्तांतरणकर्ता के जिसने अच्छे विश्वास में और मूल अनुबंध की सूचना के बिना अपना पैसा चुकाया है;

(सी) एक शीर्षक के तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति जो, हालांकि अनुबंध से पहले और वादी को ज्ञात था, प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था;

1[(सीए) जब एक सीमित देयता भागीदारी ने एक अनुबंध में प्रवेश किया है और बाद में एक अन्य सीमित देयता भागीदारी के साथ समामेलित हो जाती है, तो समामेलन से उत्पन्न होने वाली नई सीमित देयता भागीदारी।]

(डी) जब एक कंपनी ने एक अनुबंध में प्रवेश किया है और बाद में एक अन्य कंपनी के साथ समामेलित हो जाती है, तो समामेलन से उत्पन्न होने वाली नई कंपनी;

(ई) जब एक कंपनी के प्रवर्तकों ने, इसके निगमन से पहले, कंपनी के उद्देश्य के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया है और ऐसा अनुबंध निगमन के नियमों द्वारा वारंट किया गया है, तो कंपनी:

बशर्ते कि कंपनी ने अनुबंध को स्वीकार कर लिया है और अनुबंध के दूसरे पक्ष को ऐसी स्वीकृति सूचित कर दी है।"

13. घोषणा और रद्द करने के लिए एक वाद के बीच के अंतर को *सुहरिद सिंह @ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य* (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त रूप से समझाया गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार हैं:

"6. जहां एक विलेख का निष्पादक इसे रद्द करना चाहता है, उसे विलेख को रद्द करने की मांग करनी होगी। लेकिन अगर एक गैर-निष्पादक एक विलेख को रद्द करने की मांग करता है, तो उसे एक घोषणा की मांग करनी होगी कि विलेख अमान्य है, या गैर-मौजूद है, या अवैध है या कि यह उस पर बाध्यकारी नहीं है। एक हस्तांतरण/विलेख के संबंध में रद्द करने और घोषणा के लिए एक प्रार्थना के बीच का अंतर 'ए' और 'बी' - दो भाइयों से संबंधित निम्नलिखित उदाहरण द्वारा लाया जा सकता है। 'ए' 'सी' के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित करता है। बाद में 'ए' बिक्री से बचना चाहता है। 'ए' को विलेख को रद्द करने के लिए मुकदमा करना होगा। दूसरी ओर, यदि 'बी', जो विलेख का निष्पादक नहीं है, इससे बचना चाहता है, तो उसे एक घोषणा के लिए मुकदमा करना होगा कि 'ए' द्वारा निष्पादित विलेख अमान्य/शून्य और गैर-मौजूद/अवैध है और वह इससे बाध्य नहीं है। सार में दोनों विलेख को रद्द करने या गैर-बाध्यकारी घोषित करने के लिए मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन रूप अलग है और कोर्ट फीस

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

भी अलग है। यदि 'ए', विलेख का निष्पादक, विलेख को रद्द करने की मांग करता है, तो उसे बिक्री विलेख में बताए गए विचार पर एड-वेलोरम कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा। यदि 'बी', जो एक गैर-निष्पादक है, कब्जे में है और एक घोषणा के लिए मुकदमा करता है कि विलेख शून्य या अमान्य है और उसे या उसके हिस्से को बाध्य नहीं करता है, तो उसे अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17(iii) के तहत केवल ₹19.50 की एक निश्चित कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा। लेकिन यदि 'बी', एक गैर-निष्पादक, कब्जे में नहीं है, और वह न केवल एक घोषणा की मांग करता है कि बिक्री विलेख अमान्य है, बल्कि कब्जे की परिणामी राहत भी, तो उसे अधिनियम की धारा 7(iv)(c) के तहत प्रदान की गई एक एड-वेलोरम कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा। धारा 7(iv)(c) यह प्रावधान करती है कि परिणामी राहत के साथ एक घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद में, कोर्ट फीस उस राशि के अनुसार संगणित की जाएगी जिस पर वाद पत्र में मांगी गई राहत का मूल्यांकन किया गया है। इसका परंतुक यह स्पष्ट करता है कि जहां परिणामी राहत के साथ घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद किसी भी संपत्ति के संदर्भ में है, तो ऐसा मूल्यांकन धारा 7 के खंड (v) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से संगणित संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा।

07. इस मामले में, बिक्री विलेखों को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना एक घोषणा के लिए है कि विलेख "सह-अधिकार" और संयुक्त कब्जे के लिए बाध्य नहीं हैं। वाद में वादी बिक्री विलेखों का निष्पादक नहीं था। इसलिए, कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7(iv)(c) के तहत संगणनीय थी। इसलिए ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय यह मानने में उचित नहीं थे कि प्रार्थना का प्रभाव बिक्री विलेखों को रद्द करने की मांग करना था या इसलिए कोर्ट फीस का भुगतान बिक्री विलेखों में उल्लिखित बिक्री विचार पर किया जाना था।"

14. उपरोक्त का सार यह है कि यदि प्रार्थना एक विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए है, तो कोर्ट फीस का भुगतान विक्रय विलेख के मूल्य पर किया जाना है जबकि, यदि यह एक घोषणा के लिए है कि विक्रय विलेख वादी के संबंध में शून्य और अमान्य घोषित किया जाए, तो कोर्ट फीस की गणना मुख्य राहत पर की जानी है। जिन निर्णयों पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वे ऐसे मामले थे जहां दावा की गई राहत विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए थी। जो प्रश्न हमारे विचार के लिए तैयार किया गया है, वह ऐसा मामला नहीं है जहां विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए कोई राहत मांगी गई है, बल्कि मांगी गई राहत विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए है।

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

15. दिलीप बस्तिमाल जैन बनाम बाबन भानुदास कांबले और अन्य: **एआईआर 2002 बॉम 279** में, यह माना गया था कि एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद में, एकमात्र आवश्यकता बाद के हस्तांतरणकर्ता को प्रतिवादी के रूप में शामिल करना है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 48 के मद्देनजर घोषणा के लिए सहायक राहत की प्रार्थना करना और उस पर कोर्ट फीस चिपकाना आवश्यक नहीं है।

16. 1961 के अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) का परंतुक स्पष्ट शब्दों में केवल मुख्य राहत पर शुल्क लगाने का प्रावधान करता है न कि सहायक राहत पर।

17. हम इस विचार से हैं कि एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद में, बाद के विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की राहत एक सहायक राहत है, स्वयं प्रश्न में, जिसे तैयार किया गया है, इसे एक सहायक राहत के रूप में उल्लेख किया गया है।

18. *सुहरिद सिंह @ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य* (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, जो प्रश्न तैयार किया गया है, वह यह है कि क्या विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए मांगी गई राहत केवल बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मुख्य राहत के लिए सहायक होने के कारण, 1961 के अधिनियम की धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार केवल मुख्य राहत पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा, यह अब *अछूता मामला* नहीं है और चूंकि, मुख्य राहत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है और विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की प्रार्थना एक सहायक राहत है, तो कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत पर देय होगी। हम तदनुसार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब मांगी गई राहत एक सहायक राहत है, तो वादी को केवल मुख्य राहत पर ही कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है और उसे 1961 के अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार विशिष्ट और अलग-अलग राहत के कुल मूल्य का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

19. प्रश्न संख्या 2 के संबंध में, हम इस विचार से हैं कि उक्त प्रश्न को ठीक से तैयार नहीं किया गया है। जो प्रश्न तैयार किया गया है, उसके अनुसार, एक विशिष्ट राहत के लिए एक वाद में, प्रश्न यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि वाद पत्र में क्या राहत मांगी गई है। हालांकि, प्रश्न में यह उल्लेख है कि यदि वादी के पक्ष में बिक्री के समझौते के बाद निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने की प्रार्थना है, तो 1961 के अधिनियम की धारा 38 के अनुसार विक्रय विलेख में घोषित संपत्ति के मूल्य पर

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(

मूल्य के अनुसार आधार पर कोर्ट फीस देय है। यह कहना पर्याप्त है कि विक्रय विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए वाद विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए एक वाद नहीं है, इसलिए, 1961 के अधिनियम की धारा 38 लागू नहीं होगी और एड-वेलोरम कोर्ट फीस देय नहीं है। हालांकि प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन हम इसका उत्तर नकारात्मक में देते हैं।

20. संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया गया है। मामले से अलग होने से पहले, हम बार के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करना चाहेंगे।

(भुवन गोयल), जे (पंकज भंडारी), जे

सुनील सोलंकी /पीएस

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(29/05/2025 को 12:04:36 PM पर डाउनलोड किया गया(